

सितंबर में ऑटो सेक्टर ने मचाया धमाल

मारुति की बिक्री 24 फीसदी बढ़ी, हुंडई की मासिक बिक्री रिकॉर्ड स्तर पर

नवभारत न्यूज नेटवर्क. नयी दिल्ली, 2 अक्टूबर। देश की प्रमुख ऑटो कंपनियों ने सितंबर 2026 के अपनी बिक्री के आंकड़े जारी कर दिए हैं. भारतीय ऑटो सेक्टर के लिए बिक्री के आंकड़े काफी मजबूत रहे. हुंडई ने जहां अपनी अब तक की सबसे ज्यादा मासिक बिक्री दर्ज की, वहीं महिंद्रा एंड महिंद्रा और जीएएसडब्ल्यू एमपी मोटर इंडिया ने भी सालाना आधार पर अच्छी ग्रोथ दर्ज की.

इसके साथ ही मारुति की बिक्री में भी उछाल आया. मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड की सितंबर में कुल बिक्री 24.4 प्रतिशत बढ़कर 2,36,013 इकाई हो गई, जबकि पिछले साल इसी



महीने में यह 1,89,665 इकाई थी. देश की प्रमुख मोटर वाहन विनिर्माता कंपनी ने गुरुवार को बताया कि कुल बिक्री के आंकड़े में घरेलू बिक्री, निर्यात और अन्य मूल उपकरण विनिर्माताओं को की गई बिक्री शामिल है. मारुति सुजुकी इंडिया ने शेयर बाजार को भी सूचना में कहा कि पिछले महीने

कुल घरेलू यात्री वाहन बिक्री करीब 37 प्रतिशत बढ़कर 1,81,838 इकाई हो गई जो एक साल पहले इसी महीने में 1,32,820 इकाई थी.

टाटा मोटर्स- टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड की सितंबर में कुल बिक्री 15 प्रतिशत बढ़कर 70,210 इकाई हो गई.

कंपनी ने पिछले साल इसी महीने 60,907 वाहन बेचे थे. कुल बिक्री में इलेक्ट्रिक वाहन भी शामिल है. टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड ने कहा कि यात्री वाहनों की घरेलू बिक्री सितंबर में 15 प्रतिशत बढ़कर 68,810 इकाई हो गई, जबकि सितंबर, 2025 में यह 59,667 इकाई थी. पिछले महीने यात्री वाहनों की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बिक्री 13 प्रतिशत बढ़कर 1,400 इकाई रही, जबकि पिछले साल सितंबर में यह 1,240 इकाई थी. हुंडई मोटर- हुंडई मोटर इंडिया की निर्यात सहित कुल मासिक बिक्री सितंबर में सालाना आधार पर 10.8 प्रतिशत की वृद्धि के साथ अब तक के उच्चतम स्तर 77,916 इकाई पर पहुंच गई. मोटर

बजाज ऑटो बजाज ऑटो की निर्यात समेत कुल बिक्री सितंबर में पांच प्रतिशत बढ़कर 5,38,443 इकाई हो गई. कंपनी ने सितंबर 2025 में 5,10,504 वाहनों की बिक्री की थी. मोटर वाहन विनिर्माता कंपनी ने कहा कि दोपहिया और वाणिज्यिक वाहन सहित कुल घरेलू बिक्री पिछले महीने 9 प्रतिशत घटकर 2,94,456 इकाई रह गई. सितंबर 2025 में यह 3,25,252 इकाई थी .इसमें घरेलू दोपहिया वाहनों की बिक्री 2,39,771 इकाई रही जो सितंबर 2025 की 2,73,188 इकाई की तुलना में 12 प्रतिशत कम है.

वाहन विनिर्माता कंपनी ने बताया कि सितंबर में घरेलू बिक्री 57,166 इकाई रही, जो सालाना आधार पर 10.9 प्रतिशत अधिक है.



जीएसटी में आया उछाल

पीएमआई ने पकड़ी रफ्तार

- ▶ सितंबर में जीएसटी संग्रह 2.03 लाख करोड़
- ▶ पीएमआई सात महीने के उच्चतम स्तर पर

नवभारत न्यूज नेटवर्क. नयी दिल्ली, 2 अक्टूबर. भारतीय इकोनॉमी के लिए आज 2 बड़े आंकड़े सामने आए, जो बूस्टर डोज साबित हो सकते हैं. दरअसल सितंबर का महीना मजबूत संकेत लेकर आया है. एक तरफ ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन लगातार तीसरे महीने 2 लाख करोड़ रुपये के पार रहा तो दूसरी तरफ मैनुफैक्चरिंग सेक्टर की रफ्तार भी तेज हुई है.

सितंबर में भारत का मैनुफैक्चरिंग पीएमआई बढ़कर 7 महीने के उच्चतम स्तर 55.1 पर पहुंच गया. जीएसटी कलेक्शन में तेज बढ़ोतरी और फेडरियों में बढ़ते ऑर्डर-प्रोडक्शन को अर्थव्यवस्था में मजबूत गतिविधियों के संकेत

के तौर पर देखा जा सकता है. सितंबर 2026 में देश का ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन सालाना आधार पर 14.7% बढ़कर 2,03,521 करोड़ रुपये पहुंच गया. खास बात ये है कि जीएसटी कलेक्शन लगातार तीसरे महीने 2 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े से ऊपर रहा है. चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही यानी अप्रैल से सितंबर 2026 के दौरान कुल संघीय ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन 12,46,278 करोड़ रुपये रहा.

एक साल पहले की समान अवधि के मुकाबले इसमें 11.6% की बढ़ोतरी हुई है. यानी वित्त वर्ष की पहली छमाही में भी टैक्स कलेक्शन की रफ्तार मजबूत बनी हुई है. 7 को कार्डसिल की बैठक : इस बीच 7 अक्टूबर को जीएसटी कार्डसिल की बैठक होने वाली है. दिए गए इनपुट के मुताबिक इस बैठक में दरों में बड़े बदलाव के बजाय प्रोसेस रिफॉर्म पर ज्यादा फोकस रहने की संभावना है.

एंथ्रोपिक का नवंबर में आ सकता है आईपीओ

- ▶ नवंबर मध्य तक लिस्टिंग की तैयारी
- ▶ 2025 में 4.6 अरब डॉलर रहा राजस्व



नवभारत न्यूज नेटवर्क. नई दिल्ली, 2 अक्टूबर . आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया की प्रमुख कंपनियों में शामिल एंथ्रोपिक अब शेयर बाजार में उतरने की तैयारी तेज कर रही है. कंपनी नवंबर के मध्य तक प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) ला सकती है.

रिपोर्टों के मुताबिक, एंथ्रोपिक 9 नवंबर से शुरू होने वाले सप्ताह में संभावित निवेशकों के बीच आईपीओ की मार्केटिंग शुरू कर सकती है और इसके बाद नवंबर के

मध्य में शेयरों की ट्रेडिंग शुरू होने की संभावना है. हालांकि, कंपनी ने अभी आईपीओ की अंतिम तारीख घोषित नहीं की है और समयसीमा में बदलाव संभव है.

एंथ्रोपिक के आईपीओ की सबसे बड़ी चर्चा इसकी संभावित वैल्यूएशन को लेकर है. बाजार से जुड़े स्रोतों के अनुसार कंपनी का मूल्यांकन 1.8 ट्रिलियन से 2 ट्रिलियन डॉलर के बीच हो सकता है. इस स्तर का मूल्यांकन इसे दुनिया के सबसे बड़े आईपीओ में शामिल कर सकता है.

त्योहारों से पहले दालों पर घटेगी ड्यूटी

- ▶ मसूर पर 10, पीली मटर पर 30% शुल्क
- ▶ अरहर-उड़द मार्च 2027 तक शुल्क मुक्त



नयी दिल्ली , 2 अक्टूबर. भारत सरकार देश में बढ़ती हुई महंगाई को कम करने के लिए तमाम कोशिशें कर रही है. लेकिन खाने- पीने की चीजों के दामों में इतनी तेजी से इजाफा हो रहा है कि आम जनता परेशान है.

अधिकतर घरों में रोज बनने वाली दाल की कीमतों में भी भारी इजाफा हो रहा है. जिसको कंट्रोल

सरकार अगर आयात शुल्क घटाती है तो इसका फायदा मसूर दाल और पीली मटर को मिल सकता है. हालांकि, चना को इस छूट से बाहर रखा जा सकता है. फिलहाल भारत में मसूर और चने के आयात पर 10% टैक्स, जबकि पीली मटर पर 30% आयात शुल्क लगता है. वहीं, अरहर और उड़द के आयात को मार्च 2027 तक शुल्क फ्री किया गया है.

दालों के आयात पर लगने वाला टैक्स कम करने पर विचार जरूर किया जा रहा है.

गांधी जयंती पर सोना-चांदी के दामों में मामूली बदलाव

नवभारत न्यूज नेटवर्क. नयी दिल्ली , 2 अक्टूबर. करीब 20 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट आई है, जबकि चांदी के भाव में करीब 40 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी दर्ज की गई. दिल्ली में 24 कैरेट सोना 1,50,540 रुपए और 22 कैरेट सोना 1,37,995 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है.

देश के प्रमुख शहरों में भी सोने के भाव में मामूली अंतर देखने को मिला. मुंबई, कोलकाता और

बंगलुरु में 24 कैरेट सोना 1,50,390 रुपए तथा 22 कैरेट 1,37,845 रुपए प्रति 10 ग्राम है. अहमदाबाद और भोपाल में 24 कैरेट सोने का भाव 1,50,440 रुपए और 22 कैरेट 1,37,895 रुपए प्रति 10 ग्राम है. वहीं जयपुर और लखनऊ में 24 कैरेट सोना 1,50,540 रुपए तथा 22 कैरेट 1,37,995 रुपए प्रति 10 ग्राम है.

चांदी की कीमत में आज मामूली तेजी रही. अधिकांश शहरों में चांदी 2,26,570 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर पहुंच गई.

किसान विकास पत्र में 7.5 प्रतिशत ब्याज 1,000 से शुरू करें निवेश, 115 महीने में मिलेगा दोगुना पैसा

नवभारत न्यूज नेटवर्क. नई दिल्ली, 2 अक्टूबर . सुरक्षित निवेश के साथ तय रिटर्न की तलाश करने वाले लोगों के लिए डाकघर की किसान विकास पत्र (केवीपी) योजना एक विकल्प है. अक्टूबर-दिसंबर 2026 तिमाही में इस योजना पर 7.5 प्रतिशत सालाना ब्याज मिल रहा है.

इसमें निवेश की रकम 115 महीने यानी 9 साल 7 महीने में दोगुनी हो जाती है. योजना में न्यूनतम 1,000 से निवेश शुरू



किया जा सकता है, जबकि अधिकतम निवेश की कोई सीमा निर्धारित नहीं है. केवीपी में एकमुश्त रकम जमा करनी होती है. मौजूदा ब्याज दर और तय अवधि के आधार पर निवेश की राशि मैच्योरिटी पर दोगुनी हो

जाती है. उदाहरण के तौर पर, अगर कोई व्यक्ति 2,000 निवेश करता है तो 115 महीने बाद उसे 4,000 मिलेंगे. इसी तरह 3,000 का निवेश मैच्योरिटी पर 6,000 हो जाएगा. हालांकि, समय से पहले खता बंद करने की स्थिति में मिलने वाली रकम अलग हो सकती है.

केवीपी में 10 साल या उससे अधिक उम्र का भारतीय नागरिक अपने नाम से खता खोल सकता है. नाबालिग के लिए भी वयस्क की ओर से खता खोला जा सकता है.

समाचार विशेष

गेहूं-चावल की धीमी उठान पर मान सरकार चिंतित

नवभारत न्यूज नेटवर्क. चंडीगढ़, 2 अक्टूबर. पंजाब में अनाज की धीमी लिफ्टिंग को लेकर राज्य सरकार की चिंता बढ़ गई है. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र सरकार से अक्टूबर में पंजाब से 21 लाख मीट्रिक टन अनाज तत्काल उठाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निदेश जारी करने की मांग की है. इसमें 15 लाख मीट्रिक टन गेहूं और छह लाख मीट्रिक टन चावल शामिल हैं.

सरकार का कहना है कि समय पर स्टॉक बाहर नहीं निकला तो खरीफ विपणन सीजन 2026-27 में धान की खरीद और भंडारण के लिए जगह की समस्या पैदा हो सकती है.मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, मान ने केंद्र को भेजे पत्र में एक से 10 अक्टूबर के बीच छह लाख मीट्रिक टन चावल की आवाजाही सुनिश्चित करने को



केंद्र से मांगी तत्काल मदद कहा है. इसके अलावा पूरे अक्टूबर के दौरान 15 लाख मीट्रिक टन गेहूं उठाने की मांग की गई है.

मुख्यमंत्री ने कहा है कि राइस मिलों और मंडी परिसरों में मौजूद गेहूं के स्टॉक को अक्टूबर में बाहर निकालना जरूरी है. ऐसा नहीं होने पर आगामी धान खरीद के लिए भंडारण क्षमता प्रभावित हो सकती है. पत्र में आशंका जताई गई है कि जगह की कमी के कारण राइस मिलर्स धान के आर्वटन, भंडारण और मिलिंग के लिए आगे आने में परेशानी जता सकते हैं.

सितंबर में उठान की रफ्तार रही कम

आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक सितंबर 2026 में 29 तारीख तक पंजाब से 8.30 लाख मीट्रिक टन चावल और 4.30 लाख मीट्रिक टन गेहूं की ही लिफ्टिंग हो सकी. इससे पहले जून में कुल 11.91 लाख, जुलाई में 11.60 लाख और अगस्त में 12.72 लाख मीट्रिक टन अनाज उठाया गया था. सितंबर का कुल आंकड़ा 12.60 लाख मीट्रिक टन रहा.मुख्यमंत्री ने केंद्र से खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग और भारतीय खाद्य निगम मुख्यालय के संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देने का अनुरोध किया है, ताकि तय समय में अनाज की आवाजाही सुनिश्चित हो सके.मान ने पत्र में कहा है कि समय पर लिफ्टिंग होने से खरीफ विपणन सीजन 2026-27 के दौरान धान खरीद का संवांलन सुचारु रखने में मदद मिलेगी.

वरुण गांधी का खत्म होगा सियासी वनवास मोदी को बताया पिता तुल्य, क्या मिलने वाला है राज्यसभा गिफ्ट ?

लखनऊ, 2 अक्टूबर. उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूर्व भाजपा सांसद वरुण गांधी के नाम की चर्चा एक बार फिर तेज हो गई है. 2024 के लोकसभा चुनाव में पीलीभीत से टिकट कटने के बाद से वरुण गांधी सक्रिय चुनावी राजनीति से दूर हो गए थे.

अब 16 अक्टूबर को होने वाले यूपी की 10 राज्यसभा सीटों के चुनाव से पहले मोडिया रिपोर्टों में उनका नाम बीजेपी के संभावित उम्मीदवारों में शामिल बताया जा रहा है. ऐसे में सवाल है कि क्या वरुण गांधी राज्यसभा के रास्ते



उनकी संसद में वापसी हो सकती है. आखिर इसके पीछे कहानी क्या है ?

उत्तर प्रदेश में होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा के संभावित उम्मीदवारों की सूची में वरुण गांधी का नाम काफी आगे

चल रहा है. टिकट कटने के बाद से चर्चा थी कि वरुण गांधी बीजेपी आलाकमान से नाराज चल रहे हैं. लेकिन इन तमाम अटकलों पर विराम तब लगा जब मार्च 2026 में वरुण गांधी ने अपनी पत्नी यामिनी और बेटी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक बेहद खास मुलाकात की. मुलाकात के बाद वरुण ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा कीं और प्रधानमंत्री के प्रति सम्मान जाहिर किया. उन्होंने लिखा था कि परिवार सहित श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन पाने का सौभाग्य मिला.

2024 में पीलीभीत से कट गया था टिकट

वरुण गांधी के लिए राज्यसभा की मौजूदा चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने उन्हें पीलीभीत से टिकट नहीं दिया था. वरुण 2019 में इसी सीट से भाजपा के टिकट पर लोकसभा पहुंचे थे. 2024 में भाजपा ने पीलीभीत से जितिन प्रसाद को उम्मीदवार बनाया था. इसके बाद वरुण गांधी लोकसभा चुनाव नहीं लड़े. इस घटनाक्रम के बाद वह सक्रिय चुनावी राजनीति में पहले की तरह नजर नहीं आए.

विशेष भाजपा की अग्निपरीक्षा लेगी सपा की सोशल इंजीनियरिंग की पिछ

उप्र में वोट बैंक बचाने की लड़ाई

लखनऊ, 2 अक्टूबर. उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब खास तारीखों का जिक्र आएगा तो 4 जून 2024 की भी जरूर चर्चा होगी. इस दिन 18वीं लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आए थे. नतीजों से पहले आए एग्जिट पोल में सरकार में एनडीए की प्रचंड जीत के साथ वापसी का अनुमान लगाया गया था.

एग्जिट पोल में उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 60 से ज्यादा सीटे मिलती हुई दिखाई जा रही थीं. लेकिन असल में जब नतीजें सामने आए तो सारे एग्जिट पोल गलत साबित हुए. समाजवादी पार्टी, अकेले 37 सीटें जीतकर सूबे की सबसे बड़ी पार्टी बनकर



उभरी और 2019 में 62 सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी महज 33 सीटों पर सिमट गई. इससे पहले राज्य में हुए दो लोकसभा और दो विधानसभा चुनाव में भाजपा ने प्रचंड जीत हासिल



की थी. 2024 में अखिलेश यादव के सामाजिक ताने- बाने में भारतीय जनता पार्टी फंसी हुई नजर आई.

अब 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव

विनिंग फार्मूले में जुड़ंगी ये चीजें

उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव बेताब हैं. यही वजह है कि, 2024 में अपने विनिंग फार्मूले पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) में एक और वर्ग को भी जोड़ना चाहते हैं. विधानसभा चुनाव से पहले अपने सियासी समीकरण को मजबूत करने में जुटे अखिलेश, अपने विनिंग फार्मूले पीडीए के साथ अगड़ी जातियां खासकर ब्राह्मण को भी जोड़ना चाहते हैं. इसके साथ ही साथ सपा, मुस्लिम-यादव-दलित मतदाताओं को अपना बैकबोन बनाना चाहते हैं. जानकारी के मुताबिक, सपा कुछ ऐसी सामान्य सीटों पर दलित उम्मीदवार खड़ा करने की है, जहां उसे मुस्लिम-यादव-दलित मतदाताओं का साथ मिले .

एक नया गणित बैठा रहे हैं. 2024 के चुनाव में अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ गठबंधन में अपने हिस्से आई 62 में से सिर्फ 5 सीटों पर यादव और 4 सीटों पर मुसलमान उम्मीदवार उतारे. जबकि 17 दलित प्रत्याशियों को मैदान में उतारा. उन्होंने 9 सवर्ण और कुल 30 ओबीसी उम्मीदवारों को टिकट दिया. नतीजों में सपा ने 37 सीटों पर जीत हासिल की.

सपा की इस जीत में सबसे बड़ा योगदान ओबीसी मतदाताओं का रहा है. सपा के 37 सांसदों में से 20 ओबीसी के हैं.

क्यों बड़ी भाजपा की चिंता!- कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक-फूंक कर पीता है...शायद ऐसा ही कुछ हाल अभी भाजपा का है. 2024 में उत्तर प्रदेश में लगे झटके के बाद भाजपा 2027 में काफी अलर्ट दिख रही है.